ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 82-84
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता की तरफ बढता कदम

दयाशंकर सिंह यादव

सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सी ०एस०एन०पी०जी० कॉलेज, हरदोई (उ०प्र०), भारत

Received- 30 .11. 2018, Revised- 06 .12. 2018, Accepted - 10.12.2018 E-mail: sambadindia@gmail.com

सारांश : *'मेक इन इंडिया' का मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है।130 करोड़ की आबादी वाले मजबूत भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा हों । नये प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत युवा वर्ग को उन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनकी विदेशों में मांग है। जिन देशों को नजर में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है, उनमें स्पेन, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और पश्चिम एशिया शामिल हैं।*

सरकार ने हर साल लगभग तीन लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रस्तामव किया है और इस प्रकार से वर्ष 2017 के आखिर तक 10 लाख ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

मुख्य शब्द – मकसद, मैन्युफैक्चरिंग, आबादी, मजबूत, विनिर्माण, परिवर्तित, रोजगार, अवसर , प्रशिक्षण ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर कहा था कि "हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी, प्रतिभावान, अनुशासित और मेहनती युवाशक्ति है और मैं दुनिया के देशों से अपील करता हूँ कि वे आएँ और भारत में बनाएँ"।

मेक इन इंडिया' कार्यक्रम प्रारम्भ करने के अवसर पर उद्यमियों की सभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एफ0डी0आई0 के लिए नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम घरेलू तथा विदेशी निर्माताओं को आकर्शित करता है। इसके माध्यम से विदेशी निवेशकों सहित भारतीय बाजार का लाभ उठाने वाली विदेशी कम्पनियों को आह्वान किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो वस्तुऍं विदेशों में निर्मित होकर भारत में बेचने आती थी। उसे अब भारत में ही निर्मित करने तथा भारतीय बाजारों में बेचने का आह्वान किया गया है। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए देश के औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली में सरलता, व्यवसायिक सरलता, सूचना एवं संचार प्रणाली की सुदृढता, सड़क, रेलवे एवं परिवहर की सुगमता तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास अति आवश्यक है। इसके लिए स्मार्ट सिटी, त्वरित रेलवे, मेट्रो रेल सेवा, विद्युत उत्पादन, सुदृढ जल प्रबन्धन तथा चुस्त–दुरूस्त प्रशासनिक व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकता है।

सात सूत्रीय प्रमुख लक्ष्य

1. मध्यावधि की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में 12–14 प्रतिशत प्रतिवर्श वृद्धि करने का लक्ष्य ।
2. देश के सकल घरेलू उत्पाुद में विनिर्माण की हिस्सेहदारी 2022 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना।
3. विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना।
4. ग्रामीण प्रवासियों शहरी–गरीब लोगों में समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण ।
5. घरेलू मूल्य व संवर्द्ध धन और विनिर्माण में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना।
6. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना।
7. भारतीय विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना।

मेक इन इंडिया को सफल बनाने में चुनौतियों–

भारत में व्यवसायिक वातावरण बहुत खराब है। व्यवसाय को शुरूआत करना सभी प्रयासों के बावजूद कठिन बना हुआ है। व्यवसायिक नीतियों कर नियमों में जटिलता कायम है। यहां छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा नही होता है। निर्माण की अनुमति की प्रक्रिया बहुत जटिल और अपारदर्शी है। विनिर्माण ढॉचे एवं आधारभूत संरचना का अभाव भी मेक इन इंडिया को सफल बनाने में बडी रूकावट है। आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में विद्युत की कमी लम्बे समय से उपलब्ध है। विद्युत वितरण के लिए निजी वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण प्रयोग नही हुआ है। देश में सुगमता से ऋण उपलब्ध न होना एक बहुत बडी समस्या हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी साहूकारों एवं महाजनों से ऊॅची दरों पर ऋण लेते है। अन्त में वे साहूकारों के चंगुल में फंस जाते है। जिससे उनका जीना दुभर हो जाता है और आने वलाी पीढियों को भी इन दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है।

योजना में घरेलू और विदेशी, दोनों निवेशकों को एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का वादा किया गया

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

है। पीएम मोदी की सोच यह थी कि भारत की 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत को एक मजबूत निर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकेंगे. भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने एवं देश की इकोनॉमी के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितम्बर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी पीएम मोदी ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई अभियान चलाए. लेकिन इन सबसे रोजगार के मोर देश में बढ़ रही बेरोजगारी और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा देश के विकास के लिए निर्णय लिए गए। सरकार द्वारा लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं भी चलाई गई, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' योजना की तरह सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नीति का भी प्रावधान रखा गया। सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य था की देश में होने वाला निर्यात को कम किया जा सके और देश में रोजगार के अवसर पैदा किये जा सके, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

मेक इन इंडिया एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि भारत के हित के लिए लिया गया है। मेक इन इंडिया का निर्णय भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 में ले लिया गया था। इसके अंदर सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनी द्वारा भारत के अंदर वस्तुओं का निर्माण हो सके इस बात पर जोर दिया गया है। 'मेक इन इंडिया' का उद्देश्य था कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके और रोजगार के अवसर निकाले जा सके। साथ ही भारत में सबसे ज्यादा होने वाले निर्यात को रोका जा सके और आयात ज्यादा किया जा सके।देश के अंदर विदेशी चीजों को बनाने की योजना चालू की गई। इस योजना का नाम "मेक इन इंडिया" रखा गया। यह एक महत्वपूर्ण नीति बनी, जिससे लोगों को बहुत से रोजगार के अवसर मिल पाये।

मेक इन इंडिया के उद्देश्य– भारत के अंदर मेक इन इंडिया नीति का चालू करना देश में बहुत से उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। इस नीति के दौरान भारत में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है की भारत के अंदर विदेशी कंपनी द्वारा निवेश किया जाए, ताकि भारत भी विदेशी उत्पादन कर सके।भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात को कम किया जाए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि देश के अंदर बढ़ने वाली बेरोजगाई को रोका जा सके और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसका एक और उद्देश्य यह भी है की कंपनियों को बढ़ावा दिया जाना है जो कि कुछ सालों के अंदर ही बंद कर दी गई। भारत के अंदर बढ़ने वाली बेरोजगारी, साक्षरता, भ्रष्टाचार, गरीबों का और गरीब होना आदि बातों को ध्यान में रखा गया। इस नीति के दौरान 100 से अधिक स्मार्ट प्रोजेक्ट चालू किए जाएंगे।

मेक इन इंडिया के लाभ– मेक इन इंडिया नीति के बनाने पर भारत देश में बहुत से लाभ हुए हैं। इस नीति के आने पर भारत में बहुत से क्षेत्रों में सुधार हुए है ।

1. भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना है ताकि यहाँ के बने उत्पादों को विश्व के किसी भी कोने में बेचा जा सके। मेक इन इंडिया के माध्यम से सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी जिससे की भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके स

2. आर्थिक विकास को बढ़ावा देना – श्मेक इन इंडियाश अभियान में बढ़ोतरी से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी। निर्यात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारत को मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के माध्यम से विनिर्माण के वैश्विक हब में बदल दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र अभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 16: का योगदान देता है और सरकार का लक्ष्य इसे 2020 तक 25 करना है

3. रोजगार के अवसर– मेक इन इंडिया नीति के बनने पर भारत देश में बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर मिले, क्योंकि भारत के अंदर बहुत से विदेशी उत्पाद और नए–नए कंपनियों का निर्माण होने लगा।जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे। सरकार द्वारा कुशल व्यक्तियों को मुद्रा योजना के अनुसार सही आय निर्धारित की गई, जिससे लोगों में काम करने की इच्छा बड़ी। नए–नए लोगों को नई नई कंपनियां शुरू करने का अवसर मिला, साथ ही साथ जिन लोगों की कंपनियां बंद हो चुकी थी उन कंपनियों को वापस शुरुआत करने का मौका मिला।

भारत के इस अभियान में उन युवा प्रतिभाओं की मदद करने की बात भी कही गयी है जो कि नवाचार और उद्यमिता कौशल में निपुण हैं ऐसे लोगों को सरकार मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता देगी जिससे कि देश में नयी स्टार्ट उप कंपनियों का विकास हो सकें जो कि आगे चलकर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे इस प्रोजेक्ट में कुल 25 क्षेत्रों के

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

विकास पर ध्यान दिया जायेगा जिससे लगभग दस मिलियन लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है यदि इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में कई और क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी जो कि कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था को समृद्धि के मार्ग पर चलाकर चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देगा

4. विदेशी निवेश– सरकार द्वारा इस योजना के तहत मुंबई के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर 68 देशों और 2500 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया।इस योजना के अंदर विदेशी कंपनियों का भारत में आकर उत्पादन करने से भारत के लोगों को निवेश करने का मौका मिला। सरकार ने 'मेक इन इंडिया वीक' का आयोजन 13 फरवरी 2016 को मुंबई में बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमएमआरडीए ग्राउंड में आयोजित किया गया था। सप्ताह के लंबे बहु क्षेत्रीय औद्योगिक में 68 देशों के 2500 अंतरराष्ट्रीय और 8000 घरेलू प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। DIPP के सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि उन्हें 15.2 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताओं और 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश पूछताछ (investment inquiriet) प्राप्त हुई थी। महाराष्ट्र को 8 लाख करोड़ रुपये (120 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश मिला

5. भारत में रक्षा– 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के माध्यम से विदेशी रक्षा कंपनियां अपने कारखानों को भारत में स्थापित करने पर विचार कर रही हैं इसी क्रम में अगस्त 2015 में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सुखोई लड़ाकू विमान के 332 पार्ट्स की तकनीक को भारत को स्थानांतरित करने के लिए रूस के इरकुट कॉर्प कम्पनी से वार्ता शुरू की। फरवरी 2017 में, लॉकहेड ने कहा कि यह भारत में स्थानीय साझीदार के साथ एफ –16 ब्लॉक –70 विमान का निर्माण करने का इरादा रखती है, अगर भारतीय वायु सेना इन विमानों को खरीदने पर सहमत हो जाती है

6. विनिर्माण हब– सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नीति लागू की गई, जिससे बहुत सी विदेशी कंपनियों को भारत में टैक्स की छूट दी गई और बहुत सी विदेशी कंपनियों को भारत के अंदर लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तॉकि भारत के अंदर बहुत सी विदेशी चीजों का निर्माण हो सके और देश में होने वाले निर्यात को रोका जा सकें। भारत को एक विनिर्माण हब बनाया गया, जिससे लोगों को बहुत से रोजगार के अवसर मिलने में मदद मिले।

7. आर्थिक विकास– 'मेक इन इंडिया' नीति के बनाने से भारत में आर्थिक रूप से बहुत सुधार हुए हैं। भारत के अंदर जैसे–जैसे नए–नए चीजों का उत्पादन किया जाने लगा, वैसे वैसे निर्यात में वृद्धि होने लगी। जैसे–जैसे भारत के अंदर भारतीय उत्पादन की मांग बढ़ती गई, वैसे–वैसे रोजगार के अवसर भी बढ़ते गए और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरती गई।

निष्कर्ष– सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से देश में बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और बहुत से व्यक्तियों को अपने बंद हुए व्यवसाय को चालू करने का मौका मिलेगा। देश में बहुत से मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा और देश का विकास किया जा सकेगा। आगे आने वाले समय में 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत में विदेशी कम्पनियाँ अपने कारखाने भारत में लगाएंगी, जिससे भारत का आयात बिल कम होगा देश में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे और भारत एक विनिर्माण क्षेत्र की नयी महाशक्ति बनकर उभरेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मेक इन इंडिया, http://www.makeinindia.com/ home
2. Bansal, Madhvi, P.M. launched Make In India Campaign to make India a manu facturing hub ,Prime Minister Narendra Modi on 25 September 2014 launched Make In India Campaign at Vigyan Bhawan in New Delhi to make India a manufacturing hub.
3. http://www.allonmoney.com/investments/make-in-india-event-narendra-modi/
4. https://www.quora.com/Make-In-India-political-program/What-is-the-Make-in-India-project
5. Kaushal, Deepa, Prakash Garg Indian Streams Research Journal International Recognized Multidisciplinary Research Journal Volume : VI, Issue : II, March - 2016 MAKE IN INDIA"- AN EMPIRICAL STUDY WITH REFERENCE TO INDIAN MANUFACTURING SECTORS

*****